IJAER/January-February-2025/Volume-14/Issue-1 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research
(Peer-Reviewed, Open Access, Fully Refereed International Journal) Impact Factor:7.06

राजनैतिक पार्टियों की वित्त व्यवस्था का एक राजनैतिक अध्ययन

डॉ.राकेश चन्द्र (असिस्टेन्ट प्रोफेसर)
राजनीति विज्ञान, राजकीय महिला महाविद्यालय छिबरामऊ, कन्नौज, उत्तर प्रदेश
rakesh7916378@gmail.com

सारांश, आज कल के माहोल में स्वस्थ लोकतांत्रिक राजनीति नागरिकों, समूहों, सार्वजनिक पद के उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के बीच सूचना के मुक्त प्रवाह पर महत्वपूर्ण रूप से निर्भर करती है। सुनने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों के बिना बोलने का अधिकार महत्वहीन हो जाता है, कैलिफोर्निया विधानसभा के अध्यक्ष जेसी अनरुह के प्रसिद्ध शब्दों में, पैसा राजनीति का माँ का दूध है, फिर भी जिस तरह से राजनीतिक धन जुटाया और खर्च किया जाता है, वह लोकतांत्रिक राजनीति की वैधता को कमजोर कर सकता है, यह सुनिश्चित करना कि पार्टियों और उम्मीदवारों के पास चुनावों में प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हों, आर्थिक असमानता की वास्तविकता और राजनीतिक समानता के आदर्श के बीच अपरिहार्य तनाव को देखते हुए समस्या ग्रस्त है। राजनीतिक समानता को कमजोर करने से धन के संकेन्द्रण को रोकने के प्रयास भाषण और संघ की आधार भूत स्वतंत्रता के साथ संघर्ष कर सकते हैं, हर लोकतंत्र राजनीतिक धन की जरूरत को उसके द्वारा उत्पन्न समस्याओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए संघर्ष करता है। किसी ने भी पूरी तरह से संतोषजनक और दीर्घकालिक समाधान नहीं पाया है, नीति निर्माताओं के लिए उपलब्ध राजनीतिक वित्त उपकरण सार्वजनिक सब्सिडी, योगदान पर सीमाएँ, व्यय नियंत्रण, प्रकटीकरण और अभियान गतिविधि का विनियमन अक्सर सुधारकों को अधूरे उद्देश्यों और अप्रत्याशित परिणामों के साथ छोड़ देते हैं।

मुख्य शब्द, सार्वजनिक सब्सिडी, पार्टी कॉकस, अवैध धन, पूंजीगत ब्रान्ड, आदि।

प्रस्तावना, राजनीति में धन की प्रमुखता और प्रकृति संस्थागत सेटिंग्स में भिन्न होती है। पार्टी–केंद्रित चुनावी प्रणाली उम्मीदवार–केंद्रित प्रणालियों से काफी भिन्न होती है। पूर्व में, जो अक्सर पश्चिमी यूरोप की संसदीय प्रणालियों से जुड़ी होती है, राजनीतिक धन का अर्थ पार्टी वित्त होता है। अधिकांश, यदि सभी नहीं, राजनीतिक निधि राजनीतिक दलों द्वारा जुटाई और खर्च की जाती है और प्राथमिक चिंताएँ पार्टी की नियमित गतिविधियों, संसद में पार्टी कॉकस के काम और चुनाव अभियानों के लिए उपलब्ध निधियों की पर्याप्तता से संबंधित हैं। पार्टियों को अक्सर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सार्वजनिक सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिसमें नकद और राज्य के स्वामित्व वाले नेटवर्क पर मुफ्त प्रसारण समय शामिल है। पार्टी के वित्त के विनियमन की सीमा में पर्याप्त भिन्नता है, जिसमें बड़े निजी योगदानों का खुलासा और भुगतान किए गए राजनीतिक विज्ञापन पर प्रतिबंध सबसे आम हैं और योगदान पर सीमाएँ सबसे कम आम हैं। पार्टी–केंद्रित प्रणालियाँ बढ़ती

अभियान लागतों और घोटालों से अछूती नहीं रही हैं, जैसा कि इटली में क्लीन हैंड्स जाँच और जर्मनी में हेल्मुट कोहल के क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स के खिलाफ हाल ही में लगाए गए आरोपों से पता चलता है। लेकिन पार्टी–केंद्रित प्रणालियों में राजनीतिक धन से जुड़ी समस्याएँ अपेक्षाकृत नियंत्रित हैं और वित्तीय प्रथाओं को आम तौर पर निगरानी और मरम्मत की जरूरत के रूप में देखा जाता है, न कि कट्टरपंथी सर्जरी की।[1] इसके विपरीत, उम्मीदवार–केंद्रित प्रणालियों में, राजनीतिक पार्टी की गतिविधि पर कम और व्यक्तिगत उम्मीदवारों द्वारा अभियान के लिए धन जुटाने और खर्च करने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इन प्रणालियों में, चुनाव का शब्द पार्टी वित्त के बजाय अभियान वित्त है। संयुक्त राज्य अमेरिका, निश्चित रूप से, लोकतंत्रों के इस वर्ग का सबसे प्रमुख उदाहरण है और इसके विभिन्न घटकों में सबसे असामान्य है। जबकि पार्टियों ने एक बार अमेरिका में उम्मीदवारों की भर्ती और अभियान चलाने पर अपना वर्चस्व स्थापित किया था, एक पेशेवर सिविल सेवा के निर्माण, प्रत्यक्ष प्राथमिक के प्रसार, टेलीविजन के उदय, पार्टी नियमों में सुधार और सार्वजनिक अधिकारियों को पर्याप्त स्टाफ संसाधनों के प्रावधान सहित कई विकासों ने उनकी भूमिका को कम कर दिया है।

भारत में पार्टी संगठन बड़े पैमाने पर मौजूदा पदाधिकारियों के उपांग बन गए हैं – स्वतंत्र राजनीतिक अभिनेताओं की तुलना में कानून की सीमाओं के भीतर और बाहर धन जुटाने के लिए अधिक साधन प्रयोग किए जाते है। भारत का चुनाव आयोग, उम्मीदवार–केंद्रित प्रणालियों में राजनीतिक धन को व्यापक रूप से अत्यधिक समस्याग्रस्त मानता है और इस पर रिपोर्टिंग करने और इसके हानिकारक प्रभावों को कम करने के सर्वोत्तम तरीकों पर बहस करने में बहुत समय और ऊर्जा खर्च की जाती है। राजनीतिक धन की मांग और आपूर्ति पार्टी या उम्मीदवार–केंद्रित चुनावों की सीमा से कहीं अधिक आकार लेती है। अमेरिका में, संघीय प्रणाली में चुनावों की विशाल संख्या, कार्यकारी और विधायी चुनावों का पृथक्करण, बहुलता नियम, मुक्त भाषण की संवैधानिक सुरक्षा, बड़े भारत में दर्शकों तक पहुँचने की उच्च लागत, अभियानों की व्यावसायिकता और लंबाई, और नीति प्रक्रिया की पारगम्यता सभी चुनाव अभियानों में जुटाई गई और खर्च की गई बड़ी रकम में योगदान करते हैं। चुनावों के कथित दांव, अभियानों में निजी संसाधनों को जुटाने और खर्च करने के लिए प्रोत्साहन और अवसर, और इसकी भूमिका को नियंत्रित करने वाले कानून और मानदंड सभी यह निर्धारित करते हैं कि लोकतंत्रों में राजनीतिक धन कैसे प्रवाहित होता है।[2]

राजनीतिक धन से जुड़ी समस्याएँ, बीसवीं सदी की शुरुआत और मध्य में बढ़ते अभियान लागत, घोटाले और इक्विटी संबंधी चिंताओं ने दुनिया भर के लोकतंत्रों में राजनीतिक वित्त के विनियमन और पार्टी और अभियान लागतों के सब्सिडीकरण की लहरों को जन्म दिया (पल्टियल 1981) इसी तरह की चिंताओं ने हाल के वर्षों में राजनीतिक वित्त के विनियमन और सब्सिडी के मुद्दों को सार्वजनिक एजेंडे पर रखा। समस्याएँ तब पैदा होती हैं जब पार्टियाँ और उम्मीदवार ऐसे समय में प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने के लिए संघर्ष करते हैं जब वे लागतें तेजी से बढ़ जाती हैं और जब समूह और व्यक्ति चुनाव परिणामों और नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करना चाहते हैं। एक चरम पर रिश्वतखोरी और जबरन वसूली है, निजी संसाधनों और सार्वजनिक प्राधिकरण का व्यक्तिगत लाभ के लिए अवैध संबंध। इस तरह के

स्पष्ट लेन–देन के अलावा, ऐसी समस्याएं हैं जैसे कि पार्टियों और उम्मीदवारों की बड़े वित्तीय योगदानकर्ताओं पर निर्भरता, राजनेताओं द्वारा विधायी या प्रशासनिक निकाय द्वारा अनुकूल कार्रवाई चाहने वालों से योगदान प्राप्त करने पर उत्पन्न होने वाले हितों के टकराव, और वित्तीय योगदानकर्ताओं द्वारा विशेष पहुंच और प्रभाव की उपस्थिति के कारण लोकतांत्रिक वैधता पर प्रभवित करते है। कैसे पार्टी और सार्वजनिक अधिकारी अपना समय आवंटित करते हैं, वे किसे देखते हैं और सुनते हैं, और दोनों सरकार की विचार–विमर्श प्रक्रियाओं को कैसे प्रभावित करते हैं।[3]

समस्याओं का एक और समूह सीधे चुनावी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। चुनाव प्रचार की बढ़ती लागत और अपर्याप्त राजनीतिक फंडिंग चुनावी प्रतिस्पर्धा को कम करती है और योग्य लोगों को सार्वजनिक पद की तलाश करने से हतोत्साहित करती है, मौजूदा पदाधिकारियों और धनी स्व–वित्तपोषित उम्मीदवारों को एक अलग लाभ देती है, और व्यक्तियों, समूहों, उम्मीदवारों और पार्टियों की आवाज को दबाकर लोकतांत्रिक जवाबदेही को कमजोर करती है, समस्याओं का एक अंतिम समूह दूसरों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करने से ही उत्पन्न होता है। चुनावों में धन के प्रवाह को बदलने के लिए डिजाइन किए गए सुधार अक्सर समान रूप से समस्याग्रस्त अप्रत्याशित परिणाम उत्पन्न करते हैं। राजनीतिक धन को बदला जा सकता है और कानूनी अड़चनें इसे आसानी से कम जवाबदेह मार्गों की ओर मोड़ सकती हैं। महत्वाकांक्षी राजनेता स्वाभाविक रूप से कमजोरियों का फायदा उठाते हैं और कानून की सीमाओं को लांघते हैं, जिससे नियामक व्यवस्था के पूर्ण पतन के अलावा प्रभावशीलता और विश्वसनीयता को भी खतरा होता है। नीति–निर्माताओं ने राजनीतिक धन से जुड़ी समस्याओं का जवाब देने में एक पारंपरिक टूलबॉक्स का उपयोग किया है, लेकिन लोकतंत्रों में उपकरणों और विशेष अनुप्रयोगों का मिश्रण व्यापक रूप से भिन्न रहा है।[4]

सार्वजनिक सब्सिडी, बढ़ती अभियान लागत और वित्तीय योगदानकर्ताओं पर अत्यधिक निर्भरता के बारे में चिंताओं के जवाब में, पार्टियों और अभियानों के लिए सार्वजनिक समर्थन लोकतंत्रों में लगभग सार्वभौमिक हो गया है, वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान (जैसे, मुफ्त प्रसारण समय, पोलिंग, मतदाता ब्रोशर और बैठक स्थान) और अप्रत्यक्ष समर्थन या योगदान के लिए कटौती या राजनीतिक विज्ञापन के लिए कम दरों के रूप में होती है।[5] सब्सिडी पार्टियों या उम्मीदवारों को दी जाती है और पार्टी के रखरखाव या अभियान व्यय की ओर निर्देशित होती है। पार्टियों को प्रत्यक्ष नकद सब्सिडी आमतौर पर चुनावी ताकत के अनुपात में आवंटित की जाती है जबकि सेवाएं और अप्रत्यक्ष सब्सिडी आमतौर पर अधिक न्यायसंगत आधार पर प्रदान की जाती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में, राष्ट्रपति पद के लिए अपने दल के नामांकन के लिए उम्मीदवारों को सार्वजनिक मिलान निधि प्रदान की जाती है जो अपेक्षित संख्या में निजी योगदान जुटाते हैं और अपने खर्च को सीमित करने के लिए सहमत होते हैं आम चुनाव के लिए प्रमुख पार्टी के उम्मीदवारों को पूर्ण सार्वजनिक अनुदान प्रदान किया जाता है जब तक कि वे कोई निजी धन जुटाने और खर्च करने के लिए सहमत नहीं होते हैं। लेकिन अधिकांश अन्य लोकतंत्रों के विपरीत, अमेरिका पार्टियों या उम्मीदवारों के लिए कोई मुफ्त प्रसारण समय और कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए कोई सार्वजनिक सब्सिडी प्रदान नहीं करता है। सार्वजनिक सब्सिडी जोखिम रहित नहीं है। वे स्थापित पार्टियों के

प्रभुत्व को मजबूत कर सकते हैं, राज्य द्वारा नियंत्रण की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, और पार्टियों के अपने जमीनी स्तर से जुड़ाव को कमजोर कर सकते हैं। बहुत कम योग्यता सीमा पर आधारित सार्वजनिक वित्तपोषण भी हाशिये के और स्पष्ट रूप से आक्रामक उम्मीदवारों और पार्टियों को प्रोत्साहित कर सकता है। पूर्ण सार्वजनिक वित्तपोषण प्रणाली निजी संसाधनों पर चुनावों और नीति को प्रभावित करने के लिए वैकल्पिक मार्ग खोजने के लिए तीव्र दबाव उत्पन्न करती है।[6]

योगदान सीमाएँ, जबकि राजनीतिक वित्तपोषण में सार्वजनिक सब्सिडी आदर्श है, ऐसे योगदान पर सीमाएँ कम होती हैं। कई लोकतंत्र पार्टियों या उम्मीदवारों को दिए जाने वाले योगदान के स्रोत या राशि पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। जो ऐसा करते हैं, उनमें विशेष स्रोतों (जैसे, सिविल सेवक, विदेशी दानकर्ता, निगम और संघ) पर प्रतिबंध सबसे आम हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में, निगमों और संघों को कई दशकों से अपने खजाने से राजनीतिक योगदान देने से रोका गया है, लेकिन वे स्वैच्छिक राजनीतिक कार्रवाई समितियाँ (PAC) बना सकते हैं, जिसके माध्यम से वे पार्टियों और उम्मीदवारों को योगदान दे सकते हैं। बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में, कॉर्पोरेट और यूनियन के खजाने से योगदान पर प्रतिबंध भी संघीय विनियमन के अधीन नहीं होने वाले राजनीतिक दलों को सॉफ्ट मनी दान के उद्भव के माध्यम से अप्रभावी हो गए हैं। कुछ देशों ने अनुमेय स्रोतों से योगदान के आकार पर वैधानिक सीमाएँ लगाई हैं, जिनमें फ्रांस, इजराइल, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। भारत में योगदान की सीमाएँ उल्लेखनीय रूप से कम हैं, खासकर तब जब 2024 में कानून द्वारा तय किए जाने पर उन्हें मुद्रास्फीति के लिए अनुक्रमित नहीं किया गया था। दान की अधिकतम सीमा के वास्तविक मूल्य में यह गिरावट राजनेताओं पर धन उगाहने की माँग और निजी दान को अन्य चैनलों के माध्यम से प्रवाहित करने के दबाव में योगदान करती है, जो आम तौर पर योगदान सीमा से जुड़ी समस्याएँ हैं।[7]

कई लोकतंत्र पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा खर्च करने पर सीमाएँ लगाते हैं, हालाँकि ये सीमाएँ अक्सर केवल थोड़े समय के लिए (जैसे, संसदीय प्रणालियों में औपचारिक अभियान) उम्मीदवारों पर लागू होती हैं, लेकिन पार्टियों पर नहीं (या इसके विपरीत), या वे राजनीतिक गतिविधि की पूरी श्रेणियों को छूट देते हैं जो चुनाव परिणामों को प्रभावित करती हैं। जापान में, डाइट के उम्मीदवारों को अभियान व्यय पर सीमाओं का सामना करना पड़ता है लेकिन ये काफी हद तक अप्रासंगिक हैं क्योंकि वे केवल 12–दिवसीय औपचारिक अभियान अवधि पर लागू होते हैं। एक सदी से भी ज्यादा समय से ब्रिटेन ने संसद के लिए व्यक्तिगत उम्मीदवारों द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्रों में किए जाने वाले खर्च को सीमित कर रखा है (और बाहरी समूहों को उनके लिए खर्च करने से प्रतिबंधित कर रखा है) लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दलों के खर्च को विनियमित नहीं किया है, जहाँ ज्यादातर कार्रवाई होती है। 2024 में अपनाया गया एक नया कानून राजनीतिक दलों द्वारा राष्ट्रीय अभियान व्यय को सीमित करता है यह आम चुनाव के दौरान बाहरी संगठनों और व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक गतिविधि के लिए खर्च की मात्रा को भी सीमित करता है। 2024 में भारत में अपनाई गई अनिवार्य व्यय सीमा को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, जबकि आम चुनावों में सार्वजनिक धन की प्राप्ति से जुड़ी स्वैच्छिक सीमाएँ बरकरार हैं। लेकिन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, राजनीतिक दल और हित समूह आम चुनाव में राजनीतिक विज्ञापनों

(जिसे मुद्दे की वकालत के रूप में जाना जाता है, लेकिन पारंपरिक चुनाव प्रचार से अलग नहीं) के जरिए इन व्यय सीमाओं को दरकिनार करने में कामयाब रहे हैं, जिनके बारे में अदालतों ने फैसला सुनाया है कि वे विनियमन के अधीन नहीं हैं।[8]

सार्वजनिक प्रकटीकरण,राजनीतिक धन के प्रवाह में पारदर्शिता को कई लोकतंत्रों द्वारा भ्रष्टाचार या प्रभावकारी गतिविधियों को रोकने के लिए अपनाया जाता है, लेकिन प्रकटीकरण व्यवस्थाओं की व्यापकता और प्रभावशीलता व्यापक रूप से भिन्न होती है। एक छोर पर ऐसी व्यवस्थाएँ हैं, जिनमें चुनाव के बाद पार्टी के व्यय पर केवल एक रिपोर्ट दाखिल करने की आवश्यकता होती है दूसरी ओर अमेरिका जैसी व्यवस्थाएँ हैं, जिनमें राजनीतिक योगदान (200 डॉलर जितना छोटा) और व्यय की रिपोर्टिंग और इस जानकारी को समय पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने के लिए विस्तृत नियम हैं, फिर भी अमेरिका में भी, चुनाव प्रचार का एक बड़ा हिस्सा प्रकटीकरण कानून की सीमाओं से बाहर है, जबकि लोकतांत्रिक दुनिया में राजनीतिक धन के प्रकटीकरण को स्वीकृति मिल रही है – उदाहरण के लिए, ब्रिटेन ने 2000 में राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले बड़े दान को सार्वजनिक रूप से प्रकट करने की आवश्यकता के साथ अपनी लंबे समय से चली आ रही प्रथा को तोड़ दिया – कुछ स्कैंडिनेवियाई देश रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को गोपनीयता के अस्वीकार्य उल्लंघन के रूप में मानते हैं।

अभियान गतिविधि का विनियमन, राजनीतिक धन की मांग को कम करने का एक तरीका कुछ महंगी अभियान गतिविधियों को प्रतिबंधित करना है। आश्चर्यजनक रूप से बड़ी संख्या में देश टेलीविजन पर भुगतान किए गए राजनीतिक विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाते हैं, हालाँकि अधिकांश देश पार्टियों को मुफ्त टेलीविजन समय के ब्लॉक के प्रावधान के साथ प्रतिबंध लगाते हैं। भारत में इस तरह के प्रतिबंध अकल्पनीय हैं, जहाँ मुक्त भाषण की गारंटी राजनीतिक संचार पर किसी भी महत्व पूर्ण प्रतिबंध को रोकती है। अन्य देशों ने यह दावा करना शुरू कर दिया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कानूनी संरक्षण उस सीमा को सीमित करता है जिस तक अभियान गतिविधि को विनियमित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलियाई उच्च न्यायालय ने 1991 के उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, जो चुनाव अवधि के दौरान राजनीतिक विज्ञापनों के प्रसारण पर रोक लगाता था, इस आधार पर कि यह राजनीतिक संचार की स्वतंत्रता के निहित अधिकार का उल्लंघन करता है।[9]

प्रवर्तन और प्रभावशीलता, राजनीतिक धन के प्रवाह को पुनर्निर्देशित करने के लिए डिजाइन किए गए किसी भी उपाय की सफलता विनियामक और सब्सिडी उपायों के विशेष मिश्रण की सरलता, व्यापकता और समयबद्धता और प्रवर्तन के तंत्र पर निर्भर करती है। आपराधिक कानूनों (जैसे, रिश्वतखोरी या जबरन वसूली) के स्पष्ट उल्लंघन के अलावा, पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा अभियान वित्त कानूनों के अक्षरशः और भावना से विचलन अक्सर दंडित नहीं होते हैं। राजनेता राजनीतिक वित्त कानूनों को लागू करने के लिए सार्वजनिक एजेंसियों में अपेक्षित अधिकार निवेश करने के लिए अनिच्छुक हैं, एक घटना जो अमेरिकी संघीय चुनाव आयोग की संरचना और संचालन द्वारा स्पष्ट रूप से चित्रित की गई है। एफईसी, जिसके छह सदस्यों में दो प्रमुख पार्टियों में से प्रत्येक से तीन–तीन सदस्य शामिल हैं, कांग्रेस के बहुत सख्त वैधानिक

और बजटीय नियंत्रण के तहत काम करता है और अक्सर विनियामक निर्णयों पर गतिरोध पैदा करता है। कई लोकतंत्रों में उचित और व्यावहारिक विनियमन, उचित आपराधिक और नागरिक प्रतिबंध, और प्रशासनिक और न्यायिक तंत्र स्थापित करना एक कठिन काम साबित हुआ है।[10]

निष्कर्ष, इन सभी कारणों से यह आश्चर्य की बात नहीं है कि राजनीतिक वित्त सुधार अक्सर भ्रष्टाचार को कम करने, धन के हितों के प्रभाव को कम करने, अभियान व्यय में वृद्धि को धीमा करने या चुनावी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने में विफल रहते हैं। भ्रष्टाचार का मुकाबला करने और लोकतांत्रिक जवाबदेही को बढ़ाने के लिए अन्य संस्थान और नीतियां अधिक प्रभावी लीवर हैं। इनमें व्यापक आर्थिक नीतियां शामिल हैं जो सार्वजनिक अधिकारियों के विवेकाधीन अधिकार को सीमित करती हैं, कानून के शासन को पोषित करने वाली संस्थाएं और प्रथायें एक स्वतंत्र न्यायपालिका राजनेताओं और सिविल सेवकों के लिए पर्याप्त वेतन और मजबूत नैतिक आवश्यकताएं पारदर्शी बजट और वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और प्रतिस्पर्धा, जवाबदेही और सत्ता के विकल्प के स्थिर पैटर्न का समर्थन करने वाली पार्टी प्रणाली सभी राजनीतिक वित्त उपाय विफल होने के लिए अभिशप्त नहीं हैं लेकिन चूंकि न तो राजनीति से सभी निजी निधियों का उन्मूलन और न ही राजनीतिक वित्त का पूर्ण विनियमन संभव या टिकाऊ है, इसलिए लोकतंत्र इन समस्याओं को हमेशा के लिए हल करने के लिए संघर्ष करते रहेंगे,

संदर्भ ग्रंथ सूची

1 अलेक्जेंडर एच ई, शिराटोरी आर (संपादक) लोकतंत्रों में तुलनात्मक राजनीतिक वित्त, वेस्टव्यू प्रेस, बोल्डर, सीआ 2022

2 कोराडो ए, मान टी ई, ऑर्टिज डी आर, पॉटर टी द न्यू कैंपेन फाइनेंस सोर्सबुक किंग्स इंस्टीट्यूशन प्रेस, वाशिंगटन, डीसी 2022

3 गनलिक्स ए बी (संपादक) उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में अभियान और पार्टी वित्त, वेस्टव्यू प्रेस, बोल्डर, सीओ 2022

4 काट्ज आर एस पार्टी संगठन और वित्त इन लेडुक एल, 2023

5 नीमी आर जी, नॉरिस पी (संपादक) लोकतंत्रों की तुलना वैश्विक परिप्रेक्ष्य में चुनाव और मतदान सेज प्रकाशन, थाउजेंड ओक्स, सीए, पीपी. 107–33, 2023

6 कॉफमैन डी भ्रष्टाचार तथ्य, विदेश नीति 107: 114–31,2022

7 पल्टिएल के.जेड. 2023 अभियान वित्त विपरीत अभ्यास और सुधार, इन बटलर डी, पेनिमन एच.आर., रैनी ए. लोकतंत्र मतदान पर अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट, वाशिंगटन, डी.सी., पृ. 138–72,

8 पोप जे. (संपादक) ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सोर्स बुक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, बर्लिन, जर्मनी, 2023

9 कांग्रेस के लिए रिपोर्ट 2023 चयनित विदेशी देशों में राष्ट्रीय चुनावों का अभियान वित्तपोषण। लॉ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, वाशिंगटन, डी.सी.

10 सोरॉफ एफ.जे. 2024 इनसाइड कैंपेन फाइनेंसरू मिथ्स एंड रियलिटीज, येल यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यू हेवन, सी.टी.